>

Title: Need to compensate the farmers of Punjab affected by the deficient south-western monsoon.

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): सभापति महोदय, बारिश की कमी की वजह से भारत के कई प्रदेशों में सूखे की परिस्थिति बनी हुई है। केन्द्र सरकार ने कई प्रदेशों को राहत देने की योजना बनाई है और कई को राहत पहुंचाई भी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष तौर से पंजाब की ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि भारत की खाद्यान आपूर्ति में पंजाब की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। पंजाब में किसान की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है क्योंकि बिजली नहीं आ रही है, बारिश बहुत कम हुई है। इसकी वजह से डीजल के पम्प सैट को इस्तेमाल करके वहां खेती-बाड़ी का काम चल रहा है। इसकी वजह से जिसे हम जोने की फसल कहते है, उसके ऊपर किसान का खर्च बहुत ज्यादा हुआ है। अगले कुछ दिनों में केन्द्र सरकार की तरफ से, हमें जो जानकारी मिली है, शायद कृषि मंत्री भी पंजाब जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्ष 2009 में जब सूखे की परिस्थिति बनी थी, तब पंजाब सरकार को 800 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिए थे। वे 800 करोड़ रुपये पंजाब सरकार को पहुंच गए लेकिन आगे किसानों में नहीं बंटे। इसकी वजह से वहां बहुत एजिटेशन हुआ और उसके बाद 50-50, 100-100 रुपये के चैक किसानों को बांटे गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार पंजाब के मुतल्लक जो भी फैसला करे, मैं मांग करता हूं कि पंजाब के किसानों को राहत देनी चाहिए। राज्य सरकार ने 2800 करोड़ रुपये की मांग की है। अगर 2800 करोड़ रुपये से ज्यादा भी देना बनता है तो वह भी दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ यह जरूर निश्चित करना चाहिए कि जो पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को जाता है, खासकर किसानों को मुआवजा देने कि लिए, वह पैसा किसानों तक पहुंचे और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि इस बार जब मुआवजा बांटा जाए तो वह एफसीआई के माध्यम से बांटा जाए जिससे वह पैसा जो केन्द्र सरकार से जा रहा है, उन किसानों के पास पहुंचे जिनको इनकी जरूरत है।

सभापति महोदय :

श्री पी.एल. पुनिया अपने आपको श्री मनीष तिवारी के विषय के साथ सम्बद्ध करते ह।